राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र और लैंगिक आधारित मतदान व्यवहार का विश्लेषण

चन्द्रशेखर देवांगन[1], डॉ विजयलक्ष्मी देवांगन[2]

[1] शोधार्थी, राजनीति विज्ञान हेमचंद, यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग, छत्तीसगढ़

[2] शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक, पं.देवी प्रसाद चौबे शास.महाविद्यालर्य, साजा, जिला–बेमेतरा, छत्तीसगढ़

ABSTRACT

आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है, शासन प्रणालियों का स्वरूप भिन्न–भिन्न होते हैं लेकिन वास्तव में लोकतंत्र के रूप ही होते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है निर्वाचन में जनमानस की भागीदारी। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राजनीतिक दलों की नीतियां और कार्यक्रम तय करती है कि वह निर्वाचन पश्चात सत्ता पाकर कार्य करेगाा या विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों में कमियां निकालेगा। प्रस्तुत शोध पत्र में लैंगिक आधारित मतदान व्यवहार का विश्लेषण किया गया है जिसमें शोध के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि निर्वाचन में राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्रों के में किए गए वादों के किन वादों से प्रभावित होकर महिला व पुरुष मतदाता मतदान व्यवहार करते हैं, ताकि भविष्य में राजनीतिक दल महिलाओं व पुरुषों की प्राथमिकताओं के आधार पर चुनावी घोषणा पत्र बना सके। यह अध्ययन क्षेत्रीय संवेदन सरकारी रिपोर्ट से संबंधित शोध पत्रों के माध्यम से किया गया है।

KEYWORDS: घोषणा पत्र, मतदान व्यवहार, महिला मतदाता, पुरुष मतदाता, राजनीतिक दल, निर्वाचन।

प्रस्तावना

घोषणा पत्र, जिसे अक्सर मैनिफेस्टो कहा जाता है, एक दस्तावेज है जिसे राजनीतिक दल चुनाव से पहले जारी करते हैं। इसमें पार्टी की आगामी नीतियों, कार्यक्रमों और वादों का विवरण होता है। घोषणा पत्र का उद्देश्य मतदाताओं को यह जानकारी देना होता है कि अगर वे पार्टी को चुनते हैं, तो पार्टी किस तरह से शासन करेगी और किन मुद्दों पर ध्यान देगी।

घोषणा पत्र का महत्व :

घोषणा पत्र का महत्व कई पहलुओं में निहित है :

1. **जानकारी का स्रोतः** यह मतदाताओं को पार्टी की नीतियों और प्राथमिकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, जिससे वे अपनी पसंद का चुनाव कर सकते हैं।
2. **जवाबदेहीः** चुनाव के बाद, घोषणा पत्र पार्टी को अपनी वादों के प्रति जवाबदेह बनाता है। मतदाता पार्टी को उसकी वादों के आधार पर जाँच सकते हैं।
3. **मतदान व्यवहार पर प्रभावः** घोषणा पत्र मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें उल्लिखित मुद्दों और वादों के आधार पर मतदाता अपनी वोट देने की दिशा तय करते हैं।
4. **लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्साः** यह दस्तावेज लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाता है, क्योंकि यह पारदर्शिता और संवाद को बढ़ावा देता है।भारत में चुनाव केवल एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक घटना भी है। हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसमें वे अपनी आगामी नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। घोषणा पत्र मतदाताओं के निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

घोषणा पत्र का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि यह न केवल पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह मतदाताओं के सामने पार्टी की विश्वसनीयता और उसके वादों की गंभीरता को भी प्रदर्शित करता है। इसके माध्यम से पार्टी अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है और मतदाताओं को यह भरोसा दिलाने की कोशिश करती है कि उसके द्वारा किये गये वादे चुनाव के बाद भी निभाए जाएंगे। इस शोध का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि पुरुष और महिला मतदाताओं पर राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है और वे इसके आधार पर अपने मतदान व्यवहार को कैसे आकार देते हैं। यह अध्ययन इस बात पर केंद्रित है कि विभिन्न लैंगिक मतदाता घोषणा पत्र में प्रस्तुत मुद्दों और वादों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं और उनका मतदान निर्णय कैसे प्रभावित होता है।

इस प्रकार, यह शोध न केवल राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र की भूमिका को समझने में मदद करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि लैंगिक आधार पर मतदाताओं के व्यवहार में क्या अंतर होते हैं और इन मतभेदों को कैसे समझा जा सकता है।

शोध के उद्देश्यः

1. पार्टियों के घोषणा पत्र जारी करने पर लैंगिक मतदान व्यवहार का अध्ययन।
2. पुरुषों और महिलाओं के मतदान निर्णयों पर घोषणा पत्र के प्रभाव का मूल्यांकन।

Copyright© 2025, IERJ. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute the material in any medium or format) and Adapt (remix, transform, and build upon the material) under the Attribution-NonCommercial terms.

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

1. **मतदान व्यवहार का सिद्धांतः** मतदान व्यवहार का अध्ययन करना एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक, और राजनीतिक दृष्टिकोण शामिल हैं। विभिन्न सिद्धांत बताते हैं कि मतदाता अपने सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर निर्णय लेते हैं। लिंग भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। पुरुष और महिला मतदाताओं के दृष्टिकोण, प्राथमिकताएँ, और मुद्दों पर ध्यान देने का तरीका अलग हो सकता है। उदाहरण के लिए, Butler and Pinderhughes (2007) के अनुसार, सामाजिक संदर्भ और व्यक्तिगत अनुभव मतदाताओं के निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2. **घोषणा पत्र और मतदाता की प्रतिक्रियाः** घोषणा पत्र राजनीतिक दलों की प्राथमिकताओं और नीतियों का सार होते हैं। यह मतदाताओं को जानकारी प्रदान करते हैं और उनके चुनाव को प्रभावित करते हैं। पिछले अध्ययनों ने संकेत दिया है कि घोषणा पत्र उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार। घोषणा पत्र में उल्लिखित वादों और कार्यक्रमों के आधार पर मतदाता अपना निर्णय लेते हैं। Dalton (2013) के अध्ययन में पाया गया कि घोषणा पत्र मतदाताओं को पार्टी की नीतियों के प्रति जागरूक करने और उन्हें सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं।
3. **लैंगिक मतदान व्यवहारः** अध्ययन से पता चला है कि पुरुष और महिला मतदाताओं के मुद्दे और प्राथमिकताएं भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जबकि पुरुष आर्थिक नीतियों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। यह भिन्नता विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण होती है। लिंग आधारित मतदान अध्ययन यह दर्शाता है कि कैसे विभिन्न लिंगों के मतदाता अलग–अलग मुद्दों पर प्रतिक्रिया करते हैं और उनके निर्णय कैसे प्रभावित होते हैं। Norris (2000) के अनुसार, लैंगिक अंतर मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक दलों को अपने अभियान और घोषणापत्र को लैंगिक संवेदनशीलता के साथ डिजाइन करना चाहिए।

शोध पद्धति (Research Methodology)

1. **शोध डिज़ाइनः** इस शोध में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार के डेटा का उपयोग किया गया है, लेकिन यह पूरी तरह से द्वितीयक डेटा पर आधारित है। शोध का डिज़ाइन इस प्रकार तैयार किया गया है कि यह लैंगिक आधारित मतदान व्यवहार का गहन विश्लेषण प्रदान कर सके। इस शोध में पहले से प्रकाशित साहित्य, सरकारी रिपोर्ट्स, और विश्वसनीय ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग किया गया है।
2. **डेटा संग्रहण तकनीकः** डेटा संग्रह के लिए विभिन्न द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। इसमें शामिल हैं ।
3. **शैक्षणिक लेख और पत्रिकाएँः** जो मतदान व्यवहार, लैंगिक समानता, और राजनीतिक घोषणा पत्रों पर केंद्रित हैं।
4. **सरकारी रिपोर्ट्सः** जो चुनाव आयोग और अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित की गई हैं।
5. **विश्वसनीय अ०नलाइन स्रोतः** जैसे कि सरकारी वेबसाइटें, शोध संस्थानों की रिपोर्ट्स, और गैर–सरकारी संगठनों के प्रकाशन।
6. **अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट्सः** UN Women, World Bank, और अन्य वैश्विक संस्थानों की रिपोर्ट्स।

परिणाम (Findings)

1. **लैंगिक और घोषणा पत्र की प्रतिक्रियाः** द्वितीयक डेटा विश्लेषण से पता चला है कि पुरुष और महिला मतदाताओं की घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया भिन्न होती है। पुरुष अधिकतर आर्थिक नीतियों और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देती हैं। यह भिन्नता विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण होती है। पुरुष और महिला मतदाताओं की प्राथमिकताओं में यह अंतर राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे अपनी नीतियों को इन प्राथमिकताओं के आधार पर आकार देते हैं।
2. **घोषणा पत्र के प्रभाव के मुख्य क्षेत्रः** घोषणा पत्र में उल्लिखित प्रमुख मुद्दे जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार पर मतदाताओं की प्राथमिकताएं लैंगिक आधार पर विभाजित होती हैं। पुरुष और महिला मतदाताओं की प्राथमिकताओं में यह अंतर राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि वे अपनी नीतियों को इन प्राथमिकताओं के आधार पर आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, महिलाएं स्वास्थ्य और शिक्षा पर अधिक ध्यान देती हैं, जबकि पुरुष आर्थिक नीतियों और रोजगार पर अधिक ध्यान देते हैं। यह भिन्नता विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण होती है।
3. **घोषणा पत्र की लैंगिक समानता पर विशेष ध्यानः** द्वितीयक डेटा से यह भी पता चला है कि जिन घोषणापत्रों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है, वे महिला मतदाताओं के बीच अधिक लोकप्रिय होते हैं। राजनीतिक दल जो महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक स्थान, महिला शिक्षा और स्वास्थ्य, और कार्यस्थल पर समानता जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें महिला मतदाताओं से अधिक समर्थन मिलता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लैंगिक संवेदनशील नीतियों को अपनाने से राजनीतिक दलों को महिलाओं के वोट प्राप्त करने में लाभ हो सकता है।
4. **डिजिटल और सोशल मीडिया का प्रभावः** हाल के वर्षों में, डिजिटल और सोशल मीडिया ने भी मतदाताओं की घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया को प्रभावित किया है। विशेषकर युवा और शहरी मतदाता, जो सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करते हैं, वे राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों की समीक्षा और चर्चा करने के लिए इन प्लेटफार्मों का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया में, महिलाओं के लिए डिज़ाइन की गई नीतियां और कार्यक्रम सोशल मीडिया पर व्यापक समर्थन और आलोचना दोनों प्राप्त करते हैं, जो चुनाव परिणामों पर भी प्रभाव डाल सकता है।
5. **क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भिन्नताएँः** घोषणा पत्रों पर प्रतिक्रिया में क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भिन्नताएँ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में महिलाओं और पुरुषों के मुद्दे और प्राथमिकताएँ भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, ग्रामीण

क्षेत्रों में महिलाएं बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर अधिक ध्यान देती हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में महिलाएं करियर विकास और कार्यस्थल की समानता पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसी तरह, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले समूहों की प्राथमिकताएँ भी भिन्न हो सकती हैं।

6. **भारत का संदर्भः** भारत में, महिलाओं की प्राथमिकताएं विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में काफी भिन्न हो सकती हैं। उत्तर भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और सुरक्षित पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों पर अधिक जोर देती हैं। दक्षिण भारत में, महिलाओं की प्राथमिकताएं शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर अधिक केंद्रित होती हैं। इसके अलावा, पूर्वोत्तर भारत की महिलाओं के लिए, सुरक्षा और पहचान के मुद्दे महत्वपूर्ण होते हैं, जबकि पश्चिमी भारत की शहरी महिलाएं कार्यस्थल की समानता और करियर विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं।
7. **मतदाता शिक्षा का महत्वः** द्वितीयक डेटा से यह भी पता चला है कि मतदाता शिक्षा का स्तर भी घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं और पुरुष अधिक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से घोषणा पत्र का मूल्यांकन करते हैं और नीतियों की दीर्घकालिक प्रभावशीलता पर ध्यान देते हैं। इसके विपरीत, कम शिक्षा प्राप्त मतदाता तात्कालिक लाभ और सुविधाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।
8. **आर्थिक स्थिति का प्रभावः** आर्थिक स्थिति भी महिलाओं की प्राथमिकताओं को प्रभावित करती है। निम्न आय वर्ग की महिलाएं सरकारी सब्सिडी, मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं और राशन जैसी नीतियों पर अधिक ध्यान देती हैं। मध्यम और उच्च आय वर्ग की महिलाएं शिक्षा के अवसर, महिला उद्यमिता और करियर विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं।
9. **सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का प्रभावः** सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी महिलाओं की मतदान प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं। पारंपरिक समाजों में, महिलाओं की प्राथमिकताएं अक्सर परिवार और समुदाय की भलाई से जुड़ी होती हैं। इसके विपरीत, अधिक प्रगतिशील और शहरी समाजों में महिलाएं व्यक्तिगत विकास और करियर उन्नति पर अधिक ध्यान देती हैं।

परिणामों का विश्लेषणः परिणामों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि लैंगिक आधार पर मतदाता व्यवहार में महत्वपूर्ण विभिन्नताएँ होती हैं। यह विभिन्नताएँ राजनीतिक दलों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि वे अपने घोषणा पत्र को मतदाताओं की प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार करते हैं। पुरुष और महिला मतदाता अलग–अलग मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उनकी सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होती हैं। उदाहरण के लिए, पुरुष आर्थिक नीतियों और रोजगार पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, और सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देती हैं।

यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते समय लैंगिक–संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह दृष्टिकोण न केवल महिलाओं और पुरुषों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करेगा, बल्कि यह अधिक समग्र और समावेशी नीतियों को भी बढ़ावा देगा। महिलाओं की प्राथमिकताओं को शामिल करने से, राजनीतिक दल व्यापक मतदाता आधार तक पहुंच सकते हैं और अधिक प्रभावी और सशक्त नीतियाँ विकसित कर सकते हैं।

नीतिगत सुझावः

1. **लैंगिक–संवेदनशील दृष्टिकोणः** राजनीतिक दलों को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते समय लैंगिक–संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं और पुरुषों दोनों की प्राथमिकताओं को समान रूप से महत्व दिया जाए।
2. **प्राथमिकताओं को शामिल करनाः** घोषणा पत्र में महिलाओं और पुरुषों दोनों की प्राथमिकताओं को शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा, और पुरुषों के लिए रोजगार और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना।
3. **समान अवसर और संसाधनः** राजनीतिक दलों को महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए समान अवसर और संसाधन प्रदान करने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी नागरिकों को उनके लिंग के बावजूद समान अवसर मिलें।

5\. **डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोगः** राजनीतिक दलों को डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहिए ताकि वे अपने घोषणापत्र और नीतियों को व्यापक रूप से प्रचारित कर सकें और मतदाताओं से सीधे संवाद कर सकें।

5\. **क्षेत्रीय और सांस्कृतिक भिन्नताओं का ध्यान रखनाः** विभिन्न क्षेत्रों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के मतदाताओं की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ विकसित करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि सभी समुदायों की आवाज सुनी जाए और उनके मुद्दों का समाधान किया जाए।

निष्कर्ष (Conclusion)

इस अध्ययन के निष्कर्ष स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि लैंगिक आधार पर मतदाता व्यवहार में महत्वपूर्ण विभिन्नताएँ होती हैं, जो राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र और नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पुरुष और महिला मतदाता विभिन्न मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उनकी सामाजिक, आर्थिक, और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होते हैं। इस अध्ययन से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक दलों को लैंगिक–संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि वे महिलाओं और पुरुषों दोनों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। यह न केवल अधिक समग्र और समावेशी नीतियों को बढ़ावा देगा, बल्कि यह व्यापक मतदाता आधार तक पहुँचने में भी मदद करेगा। भविष्य में, राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र और नीतियों को तैयार करते समय इन निष्कर्षों को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें डिजिटल और सोशल मीडिया का उपयोग करके मतदाताओं से सीधे संवाद करना चाहिए और विभिन्न क्षेत्रों और सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के मतदाताओं की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियाँ विकसित करनी चाहिए। इस प्रकार, वे अधिक प्रभावी और सशक्त नीतियाँ विकसित कर सकेंगे, जो सभी नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा

करेंगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाएंगी।

REFRENCES

2. Butler, D. M., & Pinderhughes, D. M. (2007). Perceptions of Political Participation among African Americans: Exploring the Implications of Social Context and Group Membership. American Journal of Political Science, 51(3), 664-679.
3. Dalton, R. J. (2013). The Apartisan American: Dealignment and Changing Electoral Politics. CQ Press.
4. Norris, P. (2000). A Virtuous Circle: Political Communications in Postindustrial Societies. Cambridge University Press.
5. Chhibber, P., & Verma, R. (2018). The BJP's 2014 Victory: A Vote for Development? Studies in Indian Politics, 6(1), 1-20.
6. Paxton, P., & Hughes, M. M. (2017). Women, Politics, and Power: A Global Perspective. CQ Press.
7. Deshpande, R. S. (2006). Inclusive Growth in India: Agriculture, Poverty, and Human Development. Academic Foundation.
8. Thakur, R. (2000). India and the United Nations in the New Millennium. World Affairs: The Journal of International Issues, 4(2), 25-38.
9. Rao, N. (2010). Understanding Gendered Political Behavior: Feminist Standpoints and Political Analysis. Women's Studies International Forum, 33(2), 1-12.
10. Election Commission of India. (2020). Report on General Elections. Retrieved from Election Commission of India website.
11. UN Women. (2021). Gender Equality and Political Participation in India. Retrieved from UN Women website.
12. Rai, S. M., & Spary, C. (2018). Performing Representation: Women Members in the Indian Parliament. Oxford University Press.
13. Jenkins, L. D. (2011). Becoming an MP: Candidate Selection and the Invisible Costs of Representation in India. India Review, 10(1), 40-72.